असली ताकत ◆ भारतीय युवाओं में क्षमता की कमी नहीं, आर्थिक नियोजक इसका पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं

आर्थिक तरक्की को रफ्तार देने में सक्षम युवा

लेखक एनसीएईआर में मैक्रो कंज्यूमर रिसर्च के निदेशक हैं। नेशनल यूथ रीडरशिप सर्वे-2009 के नतीजों के अहम सबक को समेटता उनका लेख।

राजेश शुक्ला

पिछले सात-आठ साल में देश में साक्षर युवाओं की तादाद में लगातार इजाफा हुआ है। आंकड़ों से यह जाहिर है। वर्ष 2001 से 2009 के बीच साक्षर युवाओं की तादाद में 2.49 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि इस दौरान आबादी में 2.08 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। लेकिन जब हम नेशनल यूथ रीडरशिप सर्वे-2009 के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो इस उपलब्धि का महत्व कम होने लगता है। देश में 33.3 करोड़ साक्षर युवा (2009) 15 साल की उम्र तक शिक्षा प्रणाली से बाहर निकल जाते हैं। यह असुविधानजनक तथ्य है, लेकिन यह ऐसा सच है जिसे नकारना मुश्किल है। आने वाले दशकों में हम जिन युवाओं पर निर्भर होने जा रहे हैं, वे शहरी होंगे(इनमें से 59 फीसदी स्नातक, 69 फीसदी स्नातकोत्तर और 86 फीसदी प्रोफेशनल डिग्रीधारी होंगे।)उनकी सामाजिक जड़ें उस वर्ग में होंगी, जिसके पास पहले से पहले से काफी सुविधाएं हैं। जिन 71 फीसदी युवाओं के पास प्रोफेशनल डिग्री होंगी, वे या तो वेतनशुदा या फिर ऐसे लोगों की संतान होंगे, जिनका अपना रोजगार है। बहरहाल 33.3 करोड़ साक्षर आबादी में से युवा पाठकों की तादाद सिर्फ 8.3 करोड़ है।

ऐसे हालात में हमारी सांस्कृतिक योजना का जोर इस साक्षरता नेटवर्क से छन कर आने वालों युवाओं को पढ़ने की आदत अपनाने के लिए प्रेरित करने पर होना चाहिए। दरअसल टोरंटो यूनिवर्सिटी में हुए भारत में लाइट रीडिंग मसलन उपन्यास, कहानी और कविता के अध्ययन की प्रवृति का जिक्र किया गया था। अध्ययन में कहा गया है कि जिस तरह की लाइट रीडिंग की बात की जा रही है, वह सामाजिक जीवन की जटिलताओं को समझने में मदद करती है। भारत में इस तरह की पढ़ाई के ट्रेंड के सामने कई चुनौतियां हैं। लेकिन सरकार की ओर से इस आनंद देने वाली या लाइट रीडिंग से पैदा होने वाले मौके को भुनाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं पहले भी अपने कॉलम में स्वतंत्रता के बाद के लाइब्रेरी आंदोलन को पुनर्जीवित करने की बातें करता रहा हूं। साथ ही यह भी जरूरी है कि सरकारी और निजी सेक्टर दोनों में किताबों के व्यापार में सुधार किया जाए। नेशनल यूथ रीडरशिप सर्वे-2009 ने कुछ ऐसी प्रवृतियों की पहचान की है, जिन्हें रेखांकित किया जाना जरूरी है।

इस लाइट रीडिंग की वजह से जिस वैज्ञानिक रुझान को खतरा पैदा होने की बात की गई है, उसमें दम नजर नहीं आ रहा है। इस सर्वे में 200000 युवाओं से बात की गई। इनमें से 25 फीसदी लोगों ने विज्ञान में काफी दिलचस्पी जताई। इसके बाद 50 फीसदी लोगों का साइंस की ओर रुझान का स्तर ठीक था। कहने का मतलब यह था कि हमारे 75 फीसदी साक्षर युवाओं ने साइंस में एक हद तक दिलचस्पी दिखाई। 20 से 24 साल के युवाओं के बीच मेडिकल रिसर्च के बारे में जानने की काफी दिलचस्पी दिखी। हर श्रेणी के युवाओं में छात्र-छात्राओं के बीच (लगभग 60 फीसदी) मेडिकल के क्षेत्र होने वाले शोधों और नई जानकारियों को जानने में बड़ी दिलचस्पी दर्ज की गई। इसके बाद वेतन हासिल करने वाले बेरोजगार युवाओं (लगभग 56 फीसदी) के बीच इस तरह की जानकारी हासिल करने की दिलचस्पी दिखी। सर्वे से पता चला कि टीवी (38)की तुलना में युवाओं में अखबार (31 फीसदी) और पत्रिकाओं (12) से जानकारी, सूचना या मेडिसिन की उपलब्धियों के बारे में जानकारी हासिल करने का रुझान ज्यादा है। सर्वे से साफ हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण अब शहरी हलकों के मुहावरे नहीं रहे। लगभग

संजय डिमरी

67.4 फीसदी भारतीय शिक्षित युवाओं (इनमें बीच में ही स्कूल या कॉलेज छोड़ने वाले दोनों शामिल हैं) ने माना कि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण गंभीर मुद्दे हैं। रायशुमारी में 80 फीसदी युवाओं ने माना कि जैव-विविधता का गंभीर खतरा है और 86.5 फीसदी का मानना था कि सरकार का पर्यावरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए गंभीर कदम उठाने चाहिए। पर्यावरणवाद के मसलों पर जानकारी के मामले में शहरी और ग्रामीण इलाकों में फासला काफी कम था। उदाहरण के लिए 73 फीसदी शहरी युवा पर्यावरण के बारे में जो महसूस करते थे, 64 फीसदी ग्रामीण युवा भी ऐसा ही सोच रहे थे। जैव विविधता के मामले में 82 फीसदी शहरी युवा चिंतित दिखे। जबकि 77 ग्रामीण युवाओं के बीच इस मामले में चेतना दिखी।

शिक्षा की कई शानदार उपलब्धियों में से एक है कि यह मौजूदा समय की विडंबनाओं को अपने अंदर समा लेती है। आजकल हमें साफ दिखता है कि बेरोजगारी की दर काफी ज्यादा है। मौजूदा शिक्षा प्रणाली और रोजगार के लिए जरूरी कौशल के बीच काफी अंतर है। लेकिन भारत का युवा अपनी अभिव्यक्ति के मौजूदा माध्यमों के बीच संतुष्ट है। उसके पास लोकतांत्रिक विकल्प हैं। उन्हें पता है कि तनाव का कैसे सामना किया जाए। नेशनल यूथ रीडरशिप सर्वे-2009 में हमने पाया कि देश में 20 लाख ग्रेजुएट और पांच लाख पोस्टग्रेजुएट बेरोजगार है। बड़ी विडंबना यह है कि ऊंची शिक्षा और बेरोजगारी का संबंध (मैट्रिकुलेशन में बेरोजगारी 5.2 और पोस्टग्रेजुएटों के बीच 9.3 फीसदी) बढ़ता जा रहा है। लगभग 13.4 करोड़ युवा किसी न किसी रोजगार में है और उनमें संतुष्टि का स्तर 58 फीसदी है। लब्बोलुआब यह है कि भारतीय युवाओं में अपनी खूबियों की मुताबिक नतीजे देने की पूरी मानसिक क्षमता है। अब यह नियोजकों पर निर्भर करता है कि वह इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं।